



Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

सेवा में

1. सभी उपायुक्त (हरियाणा राज्य में)।
2. प्रबन्धक निदेशक, हैफेड, कारपोरेट ऑफिस, सैक्टर-5, पंचकूला।
3. प्रबन्धक निदेशक, स्टेट वेयर हाउससिंग कारपोरेशन, पंचकूला।
4. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा रीजन, बेस नं० 29-32, सैक्टर-4, पंचकूला।
5. सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (हरियाणा राज्य में)।

यादि क्रमांक: एम.पी.-1/3/2025/2668

दिनांक चण्डीगढ़ 13/02/2025

**विषय:-** रबी तथा खरीफ वर्ष 2025-26 की फसलों की हैण्डलिंग के लिए (ई-टैण्डरिंग के माध्यम से) श्रम व ढुलाई ठेकेदारों की नियुक्ति करने बारे पोलिसी।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

**सामान्य शर्तें**

1. रबी तथा खरीफ वर्ष **2024-25** की फसलों की हैण्डलिंग के लिए नियुक्त किये गये श्रम व ढुलाई ठेकेदारों की कार्य अवधि दिनांक **31.3.2025** को समाप्त होने जा रही है। इसलिए हरियाणा राज्य की सभी मण्डियों में रबी तथा खरीफ वर्ष **2025-26** की फसलों की हैण्डलिंग के लिए नये सिरे से श्रम व ढुलाई ठेकेदारों की नियुक्ति ई-टैण्डरिंग के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है जिसकी कार्यवाही शीघ्र की जानी आवश्यक है। इस सन्दर्भ में टैण्डरदाताओं से अपने-2 जिले में ऑनलाईन टैण्डर आमंत्रित करने के लिए "टैण्डर नोटिस" समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु जिला स्तर पर खुला प्रचार किया जाना आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर खुला प्रचार करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा तथा सभी सम्बन्धित कार्यालयों जैसे कि सभी खरीद एजेन्सियों, मार्केट कमेटी, नगर पालिका, पंचायत घरों व खरीद केन्द्रों आदि के नोटिस बोर्डों पर टैण्डर नोटिस को चस्पा करें। जिलावार टैण्डर आमंत्रित करने के लिए टैण्डर नोटिस की प्रति भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। खरीद किए गए खाद्यान्नों जिनका भण्डारण **8 किलोमीटर** से अधिक क्षेत्र में किया जाएगा, उसका परिवहन कार्य परिवहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। गेहूं की मण्डी से भारतीय खाद्य निगम को सीधी डिलीवरी के लिए unloading का कार्य FCI द्वारा किया जाएगा।
2. विषयाधीन टैण्डर के माध्यम से नियुक्त किये गये श्रम व ढुलाई ठेकेदारों द्वारा खरीद किये गये खाद्यान्नों के उठान हेतु पर्याप्त लेबर व इसको मण्डी स्थल से **8 किलोमीटर** तक के दायरे में स्थित भण्डारण स्थलों तक पहुंचाने हेतु परिवहन कार्य श्रम व ढुलाई ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। मामले में Terms & Conditions के बिन्दु नं० 39 के अनुसार कार्यवाही की जाए। **8 किलोमीटर** के दायरे से बाहर स्थित भण्डारण/प्रेषण हेतु परिवहन कार्य परिवहन ठेकेदारों द्वारा किया जाना है, जिनके लिए अलग से टैण्डर आमंत्रित किये जा रहे हैं।
3. श्रम व ढुलाई ठेकेदारों की नियुक्तियों के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य की खरीद एजेन्सीवार/जिलावार/मण्डीवार, संयुक्त टैण्डर आमंत्रित करने तथा इनके अन्तीकरण





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

के लिए जिला टैण्डर कमेटियों का गठन भी पूर्व वर्षों की तरह निम्न प्रकार से किया गया है तथा कमेटी का कार्य टैण्डर की शर्तों में व्याखित किया हुआ है:-

क्र०	पदनाम	पद
1	उपायुक्त	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक या उन द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
3	उप मण्डल अधिकारी (ना०), जिला मुख्यालय	सदस्य
4	जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक,	सदस्य सचिव
5	भारतीय खाद्य निगम सहित राज्य की सभी खरीद एजेंसीयों के जिला प्रबन्धक	सदस्य

4. (I) वर्ष **2025-26** की रबी तथा खरीफ की फसलों की हैण्डलिंग के श्रम व ढुलाई कार्यों के बेसिक दरों (एस.ओ.आर) का विवरण अनुबन्ध 'ए' में संलग्न है। इस अनुबन्ध के भाग-1 के श्रम व ढुलाई कार्य व इनके दर मार्केट बाई लॉज अनुसार मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अलग से निर्धारित किये हुए हैं। इसलिये इन मदों के दर टैण्डरों के माध्यम से प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुबन्ध-ए के भाग-2 के श्रम व ढुलाई कार्यों के बेसिक दरों पर टैण्डरों के माध्यम से दर मांगे जाने हैं तथा टैण्डरदाताओं द्वारा भाग-2 के श्रम व ढुलाई कार्यों के बेसिक दरों पर अपने दर quote किये जाने हैं।

(II) वर्ष **2025-26** के लिए नियुक्त किये जाने वाले श्रम व ढुलाई ठेकेदारों की नियुक्तियों बारे टैण्डर की शर्तों एवं इकरारनामों का प्रारूप साथ संलग्न किया जा रहा है। टैण्डर की शर्तों में उक्त व्याखित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य तथ्य, जिन के अनुसार टैण्डर आमंत्रण तथा उन का अन्तीकरण किया जाना है, विस्तृत रूप से व्याखित किये गये हैं। अतः टैण्डर कमेटी, "टैण्डर आमंत्रण एवं उन का अन्तीकरण" टैण्डर की शर्तों अनुसार करने की कार्यवाही करे जोकि टैण्डर प्रक्रिया का ही भाग होगा। सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक यह भी सुनिश्चित करें कि ठेकेदारों से टैण्डर की शर्तों अनुसार इकरारनामा (on proper stamp paper) किया गया हो तथा उन द्वारा हस्ताक्षरित (प्रत्येक पृष्ठ) टैण्डर की शर्तों, इकरारनामों के साथ रखी गई हों।

(III) वर्ष **2025-26** हेतु श्रम व ढुलाई ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए कुछ pre-qualification conditions निर्धारित की गई हैं जो की संलग्न "Terms and Conditions" में उल्लेखित की गई हैं।

(IV) वर्ष **2025-26** में श्रम ठेकेदार के द्वारा खाद्यान्नों की ढुलाई का कार्य केवल परिवहन के अधिकृत माध्यम/साधन द्वारा परिवहन विभाग द्वारा जारी हिदायतों/नियमों अनुसार किया जायेगा।

(V) वर्ष **2025-26** के दौरान खरीद की गई फसल को मण्डी से ट्रकों में लदाई करके गोदामों/राईस मिल में भण्डारण से पूर्व प्रत्येक ट्रक की तुलाई सम्बन्धित जिला उपायुक्त द्वारा स्वीकृत उचित धर्मकांटे पर करवानी आवश्यक होगी। खरीद की गई फसल के तोल की समानता व सहीपन की सुनिश्चितता के लिए जिला नियन्त्रकों को अधिकृत किया जाता है कि वे धर्मकांटों की सूची मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा सम्बन्धित निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान से प्राप्त करें व List पर सम्बन्धित उपायुक्त की prior





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

approval लेकर स्वीकृतियां जारी करें जिन पर खरीद की गयी गेहूं की तुलवाई करवाई जानी है।

(VI) रबी तथा खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के दौरान फसल की खरीद के 24 घण्टे के अंदर आढती को फसल का उठान के लिए ऑफर करना है।

(VII) श्रम व ढुलाई ठेकेदार समयबद्ध सीमा में कार्य नहीं करेंगे तो उन पर पेनेल्टी लगाई जाएगी। यदि परिवहन ठेकेदार 3 घण्टे की समय सीमा में ट्रक उपलब्ध नहीं करवाएगा तो उस पर पेनेल्टी लगेगी। यह सारी प्रक्रिया ई-खरीद पोर्टल पर रिकार्ड की जाएगी।

5. All the tenders shall be opened in the presence of the Chairman and all the members including Member-Convener of the District Level Tender Committee. The Chairman and all the members of District Level Tender Committee (DLTC) will sign (along with date and designation) the tender form before and after finalization of the tender. The tender shall also be signed by the tenderer with the full name of the tenderer written below signature. Final rate decided by the Committee shall also be written in words.

6. As per the Government of India guidelines dated 06.05.2019, uniform SOR for the fixation of Transportation charges and finalization of economic cost will be decided by State Level Committee (SLC). Further, Provision explained in clause No. 24.

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार केन्द्र वार श्रम एवं ढुलाई की दरों की स्वीकृतियां सम्बन्धित जिला उपायुक्त के अनुमोदन उपरान्त जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें और तत्पश्चात् मुख्यालय को इस स्वीकृति की प्रति/आवश्यक सुझाव (यदि कोई हो) भिजवाना सुनिश्चित करें। कृप्या इसे परम अग्रता प्रदान करें।

संयुक्त निदेशक (मण्डी प्रोफोर्मा)

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा  
 उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

पृ० क्रमांक: एम.पी.-1/3/2025/2669

दिनांक चण्डीगढ़ 13/02/2025

उपरोक्त की एक प्रति, मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है। वर्ष 2025-26 की रबी तथा खरीफ की फसलों की हैण्डलिंग के श्रम कार्यों के ठेकेदारों की नियुक्तियों के लिये तैयार की गई टैण्डर की शर्तें एवं इकरारनामे के प्रारूप की प्रति भी सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संयुक्त निदेशक (मण्डी प्रोफोर्मा)

कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा  
 उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

पृ० क्रमांक: एम.पी.-1/3/2025/2670

दिनांक चण्डीगढ़ 13/02/2025

उपरोक्त की एक प्रति मण्डल आयुक्त, अम्बाला, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, करनाल एवं गुड़गांव को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

*Megh*  
 13/2/25

संयुक्त निदेशक (मण्डी प्रोफोर्मा)  
 कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा  
 उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

पृ० क्रमांक: एम.पी.-1/3/2025/2671

दिनांक चण्डीगढ़ 13/02/2025

उपरोक्त की एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (State Informatic Officer), एन.आई.सी., न्यू सचिवालय, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. को इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि राज्य के सभी जिलों के डी.आई.ओ. को आनलाईन ई टैंडरिंग के कार्य व्यवस्था के उचित संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें।

*Megh*  
 13/2/25

संयुक्त निदेशक (मण्डी प्रोफोर्मा)  
 कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा  
 उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

पृ० क्रमांक: एम.पी.-1/3/2025/2672

दिनांक चण्डीगढ़ 13/02/2025

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को माननीय राज्य मंत्री खाद्य एवं पूर्ति महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं पूर्ति तथा निदेशक, खाद्य एवं पूर्ति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ सचिव/माननीय राज्य मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।
3. पी.एस./निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

*Megh*  
 13/2/25

संयुक्त निदेशक (मण्डी प्रोफोर्मा)  
 कृते: निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा  
 उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

**Terms and Conditions of Labour & Cartage Tenders Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department Haryana.**

-----

1. Contractor/Tenderer should not have been blacklisted by any of the Department/Semi Government Organisation of State Government and by FCI, and not connected to any firm, which has been so blacklisted.

**Note:-** The term 'Contractor' shall mean and include the Person(s), Firm or Company with whom the contract has been placed including their heirs, executors, administrators and successors and the permitted assignees as the case may be.

2. Submission of the e-Tender documents: The tenderer shall have to deposit an amount of Rs. 1000/-plus 18% GST i.e. totalling Rs. 1180/- e-tender fee, which is non-refundable.
3. The tender shall start on dated **24.02.2025 at 9:00 am** and close on dated **03.03.2025 at 05:00 pm**.
4. Opening of e-tender: Technical bids shall be opened on dated **04.03.2025 at 9:00 am** and the financial bids of the tenderer who qualify in the Technical Bids shall be opened on dated **06.03.2025 at 2:00 pm**. These Bids shall be opened at respective district offices in the presence of the tenderer who may be present.
5. Tenderers should submit both the tender bids i.e. "Technical Bid" and "Financial Bid" only in Electronic form (Refer Tender documents). Financial Bid Proposal shall be submitted mandatorily online under commercial Envelope and original not to be submitted manually). Financial Bid only will be opened after complete Technical Bid.
6. **A tenderer/contractor should not be allotted more than 3 mandis in each district.**
7. Each Technical Bid must be accompanied by an earnest money i.e. 5% of the total cost of contract of previous year, of mandi for which tender is to be submitted through RTGS as per bank details given below:-

Name of beneficiary	District Food & Supplies Controller
Account No.	
Name of Bank	
IFSC Code	

8. Technical Bid not accompanied with the requisite amount of earnest money will be rejected. The amount of earnest money of the unsuccessful tenderer will be refunded within 5 working days from the date of tender except L2 & L3 whose EMD will be refunded within 15 working days from the date of finalisation of the tender.





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

9. The following documents are required with Technical bid:-

- i) Certified copy of Partnership Deed/Registration of Firm.
- ii) Bank statement for last six months showing turnover at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.
- iii) Letter from bank regarding credit limits enjoyed by the tenderer which should be at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.
- iv) Solvency certificate issued by the banker.
- v) Duly audited Balance Sheet/Profit & Loss account of the preceding three financial year's i.e. **2021-22, 2022-23 & 2023-24.**
- vi) Statement of Assets with valuation certificate from valuator along with documentary proof of immovable property other than residential house, which may not be less than 10% of the cost of contract value.
- vii) Tenderer will submit a certificate of satisfactory work done during previous three years in the field of mandi labour and cartage work only from the concerned DFSC/DMs of the state procurement agencies & FCI having detail of volume of work done in the mandis. Out of these three years, the tenderer should have handled the work in any one year equivalent to work to be allotted in the mandi for which he/she is submitting the tender. Further, the experience of individual partner of any partnership firm only will be considered for the experience required if it is equal to the required experience for that tender i.e. labour and construction societies work experience will not be considered.
- viii) Proof of physical availability of at least 30% trucks (as applicable) with registration in the name of tenderer firm and partners of the firm submitting the tender and for balance trucks he/she may have agreement with any transport company/truck owners with the remarks that if a firm falls short of physical availability of 30 % owned trucks, it will have to deposit an additional security@ Rs 1,25,000/- (75,000 refundable + 50,000 non-refundable) per trucks of short number of ownership of trucks after having agreement with an transport company/truck owners. However this relaxation would be given only for 10% of the shortage in owned trucks. The additional refundable security so deposited will be refundable after completion of lifting of food grains from mandi to storage points. If any firm comes L-1 in more than one tender, it will be considered for one tender only on the basis of that 30% availability of trucks details list, but if it applied with another list of 30% details (the registration number of the trucks must be different) in continuation for another mandi where it is L-1, same will be accepted for the allotment of the second tender and so on. Otherwise L-2 will be offered to work at L-1 rates. If L-2 doesn't agree, then L-3, L-4, L-5 and so on will be offered to work at L-1 rates. The same will be applicable for all the tenderers. The requirements of trucks are as under:-

Class of Mandi	Arrival/Procurement	No. of Trucks required
A	Upto 10000 MT	10





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

B	From 10001 MT to 20000 MT	20
C	From 20001 MT to 40000 MT	30
D	From 40001 MT and above.	40

Note:-1) Price bid will be opened only if the tenderer qualifies in the technical bid.

Note:-2) Previous/Projected Procurement figures of Rabi & Kharif crops may be taken from the office of the DFSC/DM concerned of the agency in District.

Note A. Copies of Registration Certificates of all the trucks mentioned in the above list along with copies of verification report generated from e-parivahan portal shall be submitted to the District Level Tender Committee on the spot (i.e. at the time of evaluation of Technical bid).

Note B. If the registration certificates of trucks submitted by the tenderer is/are found to be invalid (i.e. RCs have expired and have not been renewed etc.) capacity of the invalid vehicles shall be deducted accordingly and tender of the tenderer shall be liable to be rejected/ cancelled, if the required capacity of the relevant Mandi is not met.

Note C. During the procurement season, provision/option to add/remove the transporter details along with the vehicle detail is already available in e-kharid. Procurement Agency can unmap their respective transporter from the Mandis after closure of the respective mandi to enable his mapping as per requirement.

10. Conditional tenders will not be entertained and shall summarily be rejected by the Distt. Tender Committee.

11. If any tenderer uploads false/wrong documents while applying the tender, DLTC (District Level Tender Committee) has the authority to initiate suit for civil/criminal proceedings against the said tenderer/Contractor.

12.(a) The District Level Tender Committee reserves the right to negotiate as per Directorate of Supplies & Disposal, Govt. of Haryana Notification No. 2/2/2010-4-IB-II dated 16<sup>th</sup> June 2014 Finance Department, Haryana letter no. 14/26/2023&6FA dated 10.05.2023. In cases, the Tender Committee considers that the negotiated rates are not reasonable/ competitive/ workable; the Committee may consider cancelling and re-inviting the tenders.

(b) If there are two or more procuring agencies in a mandi, District Tender Committee should first finalise the rates of that procuring agency for which the lowest rate are quoted. Thereafter, the bidders for other agencies should be encouraged to work at the finalised rate if they do not agree, District Tender Committee reserves the right to allot the full mandi to the finalized lowest bidder of the other agency.





**Government of Haryana/हरियाणा सरकार**  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

The following provision has been made as per instructions of Finance Department, Haryana letter no. 14/26/2023&6FA, dated 10.05.2023:-

- (c) However, negotiation could be held upto four number of such bidder(s), in addition to L1 bidder in cases where there are bidders falling within 5% of the L1 bidder. In cases where the L1 bidder refuses to further reduce his offered price and any of the four bidders come forward to offer a price which is better than the price offered by L1 bidder, whose price is accepted becomes the L1 bidder.
- However, in such a situation, the original L1 bidder may be given one more opportunity to improve upon the discovered price. In case, the original L1 bidder further improve upon the price discovered during the negotiations, he would be treated as the L1 bidder.
- (d) In cases where there is no bidder within 5% of the L1 bidder:-
- (i) L2 Bidder will be invariably called for negotiation in addition to the L1 bidder.
  - (ii) L3 bidder will also be called, if it is so decided by the Minister-In-Charge, in addition to L1, L2 bidder.
13. The District Tender Committee reserves the right to accept/reject any/all tenders without assigning any reason. After the final acceptance of the tender by the tender committee, no request for further increase of rate for any operation shall be entertained.
14. The successful tenderer shall deposit the amount of security i.e. 10% of the total cost of contract of previous year, within three working days of the acceptance of his tender by the Tender Committee. The security will be deposited in the office of the DFSC/DM concerned in the District. The earnest money deposited by successful tenderer shall be adjusted in the security amount.
15. The successful tenderer shall also execute an agreement on a stamp paper with the DFSC/DM concerned within 5 working days of the acceptance of his tender. He/they shall also furnish two sureties each of equal amount of security, as above, from two reputed local persons/arthritis possessing sufficient immovable property. In case of his/their failure to do so the amount of earnest money shall stand forfeited and he/they will be black-listed and debarred for allotment of any work of the State Procurement Agencies along with FCI in future.
16. In case the lowest tenderer fails to deposit the requisite amount of security and fulfill requisite formalities as above, the DFSC/DM of the concerned agency will be competent to make an offer to the next lowest tenderer L2 & L3 with prior concurrence of the concerned Deputy Commissioner. In this regard the clauses are including:-
- (a) Earnest money of two other lowest bidders (L2 and L3) should not be returned for 15 days so that quotes of L2 and L3 can be considered in case of default of first tenderer (L1).
  - (b) Offers will be made to L2 to work at L1 rates in the eventuality of L1 not being able to work as per the terms and conditions of tenders. In case L2 is willing to





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

work at L1 rates, he will be allotted the balance work. In case of unwillingness of L-2, offer will be made to L3 to work at L1 rates. In case L3 is willing, L3 will be allotted the work at L1 rates. Should L3 not be willing, then negotiation will be held with L2 and if the rates of L2 are unreasonable, the authorities will be free to make a counter offer to L2 and if this is not accepted, the discussions with L2 will be terminated and similar negotiations will be entered with L3. The authorities may quote a counter offer here also as in the earlier case if L3 rates are unreasonable or the subsequent rates quoted by L3 are felt to be unreasonable or high. In case there is no acceptance of counter offer or if the rates in negotiations are too high, the committee may cancel the tender. Fresh local tenders will be called, if necessary, giving 24 hours notice.

- (c) However, any new contract, in case of any emergency will be awarded only after the emergency or urgency is properly justified by District Tender Committee headed by the Deputy Commissioner and approval of Director Food, Civil Supplies and Consumer Affairs is taken for this.
- (d) There will be no earnest money requirement for new contracts in case the earlier contract is cancelled on the above account.
- (e) No interest shall be payable on EMD.
17. If the successful tenderer, after depositing security amount, resiles from his offer and does not come forward for entering into an agreement with the concerned Procurement Agency within the stipulated period, then his security amount shall stand forfeited and concerned Procurement Agency will be at liberty to get the work done at his risk and cost or do the agreement with L-2 at L-1 rates.
18. If the successful tenderer after depositing security amount and entering into an agreement with the concerned State Procurement Agency, fails to undertake the work or refuses to work or make default in proper fulfillment of the conditions of the Agreement, or leave the work in between, the security deposited by him shall stand forfeited and he will be blacklisted besides being debarred from allotment of any work of the State Procurement Agencies in future. In addition, the Department/Agency shall be competent to get the remaining work carried out on the prevailing market rates/ by appointing regular contractors at the risk and cost of the defaulting contractor, by serving him with one day's notice and in that case extra amount incurred by the Department/Agency shall be recoverable from the defaulting contractor from his security and pending bills. In case any amount still remains recoverable, that would be recovered from the two sureties given by the contractor. In case the recoverable amount from the defaulting contractor still remains after the above adjustment, the exceeded amount shall be recovered from the defaulter contractor as arrears of land revenue.
19. Successful tenderer will have to start the work as and when asked by the DFSC/DM of the Agency and is required to provide sufficient labour and number of trucks as required by the Inspector-in-Charge/Purchaser of the centre, as per terms and conditions of the tender, within a time limit of 3 hours after the





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

purchase. As the stock gets ready to lift by Arthiya and verified by Inspector-in-charge/purchaser of the centre, contractor will be get the information on his login ID. Contractor will be required to provide trucks immediately and lift the stocks within 48 hours. The login Id's of the contractors will be shared by concerned DFSC/DM after allotment of tender. In case the contractor fails to provovide sufficient labour and number of trucks as per terms and conditions of tender, Rs.5,000/- per truck will be charged as penalty on the remaining stocks.

The shortage in food grains, if any, shall be borne by the Arthiya if found after first weighment (at mandi or weighbridge assigned to the concerned mandi), and by the transporter, if found after second weighment (at the storage point).

20. Contractor is also required to provide sufficient labour and transport food grains/coarse grains/stock articles from mandis/storage points as the case may be on the directions of the DFSC/DM of the concerned agencies. In addition he/she/they also will be responsible to compensate any loss caused to the Procurement Agencies for non delivery of stocks of food grains/coarse grains and stock articles at destination in time. Services of any other source will be utilized by the Department/Agency without issuing any notice to the labour and cartage contractor and payment of such operations carried out by such Company, will be made by the procuring Agency directly to that Company and the labour and cartage contractor shall have no objection or claim in this regard. By utilizing the services of such standby Company, the transport contractor will not be absolved of his liabilities/obligations under the risk and cost clause above for food grains lifted by engaging any other person/mode of conveyance. The extra expenditure payable by the procuring agency shall be recoverable from the defaulting labour and cartage contractor in due course and as per terms and conditions of risk and cost as specified above. If labour and trucks are not supplied as per demand, besides the penalty, the security amount may be forfeited. In such a case, a short notice will be issued to the defaulting labour and cartage contractor and in case of proven default/deficiency in service, the security deposited by him may be forfeited and he may be black listed besides being debarred from allotment of any work of the State Procurement Agencies in future.

- (a) No interest shall be paid on security deposit.

21. The transporter should arrange VLTD (Vehicle location and Tracking Device of AIS 140 standard as notified by MORTH on all the trucks. These VLTDs trackers shall be monitored with the assistance of a third party service provider. Movement of food grains (Wheat, Bajra, Paddy, Rice etc.) from mandis/rice mills to storage points of agencies and FCI godowns will be tracked. Hence, it is to be ensured that vehicles used for the purpose have functional VLTDs which should be registered and integrated with Software/Mobile App/Portal of service provider





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

- selected for the purpose and e-Kharid Portal. VLTD manufacturer should integrate with the Selected System Integrator (SI) for the RMS & KMS season 2025-26.
22. The contractor shall have to execute all the work to the full satisfaction of the Department/Agency. Directions for proper execution of the contract or for speedy and careful handling of foodgrains and stock articles, issued in this behalf by DFSC/DM or his representative shall be binding on him.
23. The contractor shall ensure proper building of stacks having adequate alleyways in the godowns/CAP storage of the concerned Procurement Agency as per the instructions given by their Staff. He/they shall squarely be responsible for any type of shortages of bags found from within the stacks at any subsequent stage. He/they shall also ensure that the stacks built by his/their labour are stable and do not tilt/fall. In case it happens, he/they shall be liable to get the same restacked at his/their own cost within 24 hours.
24. The contractor shall be liable to do the job of handling and local cartage work for the stocks/stock articles being received/sent from/to other centres. Contractor shall have no objection for utilizing the services of own vehicles by Government/Agencies/Societies of HAFED for procurement/lifting of stocks/stock articles.
- a) All the tenders with premium upto 10% of the SOR shall be accepted at the level of District Level Tender Committee (DLTC).
- b) If the premium is higher than 10% even after retendering. Then the proposal should be sent to the SLC for consideration/approval.
- c) No payment shall be made to the tenderer, (in case, the premium is higher than 10%) prior to the approval of rates by the State Level Committee. All payments shall be made by the concerned DFSCs/DMs of the Procuring Agencies as per the provisions of the policy.
25. The contractor will be governed by the laws of land for the time being in force in India.
26. Contractor shall comply with or cause to be complied with all the labour regulations enactments/laws made by the State Government and the Central Govt. from time to time in respect of payment of wages of the workers/labour and all related matters.
27. The contractor shall nominate/authorize in writing one or more responsible representatives who will act on his behalf in day-to-day working of the contract. The labour contractor or his representative shall contact to the office in-charge of the agency or any other officer/official acting on behalf of the agency and take instructions regarding the work to be carried out on a day-to-day basis.
28. The contractor shall take adequate steps and necessary precautions to avoid wastage and damage to the foodgrains during handling and transportation of stocks. The contractor shall be liable for any loss which the agency may suffer during handling and transportation of stocks. The contractor will be responsible





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

- for any kind of shortage of foodgrains/coarsgrains/stock articles in transit. He will also incur all charges related to labour and transportation, and toll tax etc.
29. The contractor will provide adequate number of stitchers and sweepers at his own cost at all loading/unloading and other operational points to carry out minor repairs with twine to the leakage of bags.
  30. The contractor shall collect all sweepings and spillings of food-grains at all loading/unloading and other operational points and fill them after cleaning if necessary in slack bags or in other empty bags supplied by the agencies and firmly stitch them with at least 16 stitches. The twine/thread for this purpose shall be provided by the agencies.
  31. Deduction of Income Tax and surcharge, if any, applicable shall be made at source as per law. It shall be the responsibility of the contractor to comply with the provisions of the Income Tax Act.
  32. The security will be refunded only after the successful execution of the contract. The security will be refunded on completion of internal audit of accounts for that period and if nothing is found due against him.
  33. All persons employed by the contractor shall be engaged by him as his own employees/workers in all respects and the responsibility under the Indian Factories Act or the Workmen's Compensation Act 1923 or Employees Provident Fund Act or any other similar enactments in respect of all such personnel/labour shall be only that of the contractor. The contractor shall be bound to indemnify the agency against all claims whatsoever in respect of the said personnel/labour under the Workmen's Compensation Act 1923 or any statutory modification thereof or otherwise in respect of any damage or compensation payable in consequence of any accident or injury sustained by any workmen or other person whether in employment of the contractor or not.
- (a) The Contractor shall comply with all the guidelines and instructions of Labour Department issued vide letter No. 2189-2330 dated 18.01.2019, letter no. HLWB/8666-8816 dated 17.09.2018, **the instructions issued by this office vide letter no. MP-5/5/2021/11999-12000, dated 12.07.2022** and guidelines issued by the Chief Secretary, Haryana vide their office letter No. 43/5/2001-3GS-II dated 20.02.2014 and all other instructions issued from time to time in this regard.
34. **In respect of overloading Contractor shall comply with the section 113 of The Motor Vehicle Act, 1988.**
  35. The contractor shall be liable to provide the basic facilities such as health, ESI, and Compensation etc. as per exiting law to the labourers. The contractor shall be liable to deduct and deposit at source as per rules. Further the labour contractor will be bound to pay wages as per minimum Wages Act, fixed by the Competent Authority from time to time and shall furnish an affidavit to the concerned DFSC/DM of the Agencies concerned that the payment has actually been made to the labourers for the work done by them as per wages Act.





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

- Admissible overtime will also be payable as per rules. A monthly report of statutory compliance of will be given by the Contractor to DFSC/DMs concerned.
36. That the contractor will not claim for handling of foodgrains, pulses, mustard, bajra, coarsegrain and other article stocks in the godowns under FCI guarantee scheme.
37. In case it is considered by the procuring agency that the payment made to the contractor on tendered rate is higher than the market prevailing rates, the differential amount will be recovered from his pending claims/security or otherwise.
38. In case the stocks are stored/delivered to FCI other than the purchase centre/mandi and the cartage rates are higher than the local transportation union rates/rates fixed by the DC/Department, the payment shall be restricted as per local transportation rates/rates fixed by DC/Department.
39. The work of operations contained in the Part-I of Annexure-A i.e. filling, sewing, weighing, stitching (manual machine stitching), marking on bags, temporary stacking & loading of bags on to the trucks/trolley from mandi will be given to mandi arthia association as per rates fixed by the HSAMB. They will execute agreement with DFSC/DMs of concerned agency before the scheduled date of opening of tender by District Tender Committee.
40. **In case of penalty the contractor present his appeal before First Appellate Authority i.e. DLTC if the contractor does not agree/ satisfy with the decision of DLTC then the contractor may submit his appeal before the Second Appellate Authority i.e. Director General/Director Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana/MD,HAFED/MD, HSWC.**
41. In case any dispute arises between the contractor and the State Procurement Agencies, the matter will be referred to the Director Food Civil Supplies and Consumer Affairs/M.D. of the agency concerned or his nominee for adjudicating the matter of dispute under the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 and his decision shall be binding on both the parties.
42. E-Tenderer may clearly mention his/her bank account no., name of bank and its branch along with IFSC code for refund of EMD and for labour and transportation payment in proforma 'x' given with technical bid value as per notification issued by concerned State Govt. from time to time.

*Neghar*  
13/2/25  
Joint Director (Mandi Proforma)  
for Director Food, Civil Supplies and  
Consumer Affairs Department Haryana





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

**SCHEDULE OF RATES AND SERVICES FOR LABOUR/HANDLING AND CARTAGE CONTRACTORS**

**PART-A (NoN-PREMIUM OPERATIONS)**

The contractor or casual labour, as the case may be, has to perform the work on the basic rates, without any premium, for the following operation:

**MANDI/PURCHASE CENTRE OPERATIONS**

**OPERATIONS TO BE PERFORMED BY ARHTIAS/COMMISSION AGENTS.**

Sr. No.	Particulars	As per rates already fixed by SLC and notified by Haryana State Agricultural and Marketing Board.
1	Unloading	
2	Power operated cleaning (per Sieve)	
3	Weighing & filling	
4	Stitching Manual/Machine including sutli.	
5	Loading	

SOR of Rates and Services for Labour/Handling and Cartage Contractor fixed by the SLC vide letter memo no. SOMP-1-2024/----- dated ----- as mentioned below:-

**PART-B (PREMIUM OPERATIONS)**

**1. LABOUR CHARGES FOR LOADING/UNLOADING OF FOODGRAINS**

Sr. No.	Name of Operation	(Amount in Rs. Per Hundred bags) weighing upto 40 kg.	(Amount in Rs. Per Hundred bags) Weighing > 40 upto 50 kg.
1.1	<b>Unloading of foodgrains</b> from wagons/ trucks/any other transport vehicles and directly loading on trucks/wagons/any other transport vehicles	Rs 57	Rs. 84.00
1.2	<b>Unloading of foodgrains</b> from trucks/ any other transport vehicles including stacking in open/covered storage points	Rs 86.00	Rs. 123.00
a.	Conventional Stacking in Shed/ Platform / Ground/ Up to 10 high		
b.	Upto 16 high (for actual number of Bags stacked over 10 high)	Rs. 96.00	Rs. 135.00
c.	Upto 20 high (for actual number of Bags stacked over 16 high)	Rs. 105.00	Rs. 151.00
d.	Beyond 20 high (for actual number of Bags stacked over 20 high)	Rs. 113.00	Rs. 165.00





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

2.	Breaking the Stacks and Loading of foodgrains into wagons/trucks/any other vehicles	Rs. 57.00	Rs. 84.00
----	---	-----------	-----------

**2. LABOUR CHARGES FOR LOADING/UNLOADING OF STOCK ARTICLES**

Sr. No.	Name of Operation	Rate per Stock Article
1. a.	<b>Unloading / Stacking / Removing/ loading</b> of gunny (jute)/ bales at Railway Station/godown/purchase centre (per operation)	Rs. 7.81
1. b.	<b>Unloading /Stacking/Removing/ loading</b> of tarpaulins / fumigation covers at godown/ purchase centre (per operation)	Rs. 7.81
2.	<b>Unloading / Stacking / Removing/ loading</b> of HDPE at railway station / godown/ purchase centre (per operation)	Rs. 4.95
3.	<b>Loading/Unloading of woden crates</b> from mandi/godown (per operation)	Rs. 1.32

**3. PRESERVATION AND MAINTENANCE OF ITEMS**

Sr.No.	Name of Operation	Rate
1.	<b>Coverage/removing</b> of stocks with polythene cover/tarpaulins.	Rs. 8.80/- each without tender premium
2.	<b>Mud plastering of polythene covers</b> for fumigation including cost of material i.e. clay, mud, gobri and bhusa, etc. (Maximum 4 a year) and subject to the verification of AFSO.	Rs. 22/- each operation (payment of this operation will be made to the person who actually performed the duty after verification by the AFSO himself.





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

3.	<b>Opening and closing of doors &amp; windows</b> at the time of fumigation including cost of material i.e. clay, mud, gobri & bhusa etc.	1.	Per door Rs. 4.62
		2.	Per window Rs. 3.08
		3.	Per ventilator Rs. 3.08

**4. UPGRAATION/REPLACEMENT**

Sr. No.	Name of Operation	(Amount in Rs. Per Hundred bags) weighing upto 40 kg.	Rate per Rs. Per Hundred bags) weighing upto 50 kg.
1.	<b>For carrying the Food grains bags</b> from the stacks or anywhere in the Godown premises, cutting open the mouth of bags, pouring out the contents on floor/ tarpaulins, making heaps, mixing or blending thoroughly to present desire quality, Filling the loose grains into empty gunnies upto a prescribed weight, stitching the bags in the same or another godown. Conventional Stacking in Shed/ Platform/ Ground / Up to 10 high	Rs 121.00	Rs. 171.00
a.			
b.	<b>Upto 16 high</b> (for actual number of Bags stacked over 10 high)	Rs. 133.00	Rs. 193.00
c.	<b>Upto 20 high</b> (for actual number of Bags stacked over 16 high)	Rs. 144.00	Rs. 205.00
d.	<b>Beyond 20 high</b> (for actual number of Bags stacked over 20 high)	Rs. 155.00	Rs. 218.00
2.	<b>Changing of bags</b> (reconditioning the bags) including paltai into other bag, opening sewing and weighthment. Conventional Stacking in Shed/ Platform/ Ground/ Up to 10 high	Rs. 105.00	Rs. 151.00
a.			





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

b.	<b>Upto 16 high</b> (for actual number of Bags stacked over 10 high)	Rs. 121.00	Rs. 171.00
c.	<b>Upto 20 high</b> (for actual number of Bags stacked over 16 high)	Rs. 133.00	Rs. 193.00
d.	<b>Beyond 20 high</b> (for actual number of Bags stacked over 20 high)	Rs. 145.00	Rs. 215.00

**5. STANDARDIZATION**

Sr. No.	Name of Operation	(Amount in Rs. Per Hundred bags) weighing upto 40 kg.	(Amount in Rs. Per Hundred bags) Weighing > 40 upto 50 kg.
1.	<b>For carrying the Foodgrains bags</b> from the stacks or anywhere in the Godown premises, cutting open the mouth of bags, placing on scale and weighment, sewing after pura-karai (bringing to standard weight) when rebagging is not involed and stacking Conventional Stacking in Shed/ Platform/ Ground / Up to 10 high	Rs. 105.00	Rs.151.00
a.			
b.	<b>Upto 16 high</b> (for actual number of Bags stacked over 10 high)	Rs. 121.00	Rs. 171.00
c.	<b>Upto 20 high</b> (for actual number of Bags stacked over 16 high)	Rs. 133.00	Rs. 193.00
d.	<b>Beyond 20 high</b> (for actual number of Bags stacked over 20 high)	Rs. 145.00	Rs. 215.00

**6. PHYSICAL VERIFICATION**

Sr. No.	Name of Operation	(Amount in Rs. Per Hundred bags) weighing upto 40 kg.	(Amount in Rs. Per Hundred bags) Weighing > 40 upto 50 kg.
1.	<b>Breaking/ Removing out of godown</b> weighing on platform/ beam scale and restacking in godown after physical verification of stock.	Rs. 96.00	Rs.135.00
a.	Conventional Stacking in Shed/ Platform/ Ground/ Upto 10 high.		





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

b.	<b>Upto 16 high</b> (for actual number of Bags stacked over 10 high)	Rs. 109.00	Rs.158.00
c.	<b>Upto 20 high</b> (for actual number of Bags stacked over 16 high)	Rs. 121.00	Rs.171.00
d.	<b>Beyond 20 high</b> (for actual number of Bags stacked over 20 high)	Rs. 132.00	Rs.183.00





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

**Schedule of Rate for transportation/cartage fixed by the SLC vide memo no. SOMP-3/3/2023/2059 dated 08.02.2023 as mentioned below:-**

**Cartage Charges**

Sr. No.	Distance from loading point to destination point	Rate per quintal
1	0 to 8 KM	14.3

**The break-up of 0 to 8 Kilometers as per above SOR is as under:-**

Slab	Distance from loading point to destination point.	Rate per Quintal (in Rupees)
Slab-1	>0 < 1 K.M	5.1
Slab-2	>1 <2 K.M	6.3
Slab-3	>2 < 3 K.M	7.5
Slab-4	>3 <4 K.M	8.8
Slab-5	>4 <5 K.M	10.2
Slab-6	>5 < 6 K.M	11.6
Slab-7	>6 <7 K.M	12.9
Slab-8	>7 <8 K.M	14.3

The above rate shall be applicable from 01.04.2025.





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

**Proforma of Agreement**

1. This agreement is made on \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ month of \_\_\_\_\_ year between Sh./M/s \_\_\_\_\_ (hereinafter called the first party and DFCS&CA/DM/Manager of the FCI and concerned State Procurement Agency ( hereinafter called second party).
2. The first party agrees to work as mandi labour contractor in respect of \_\_\_\_\_ mandi for doing various labour/local cartage works as per terms & conditions of the tender (enclosed).
3. That the second party has given approval of the rates given as under for which first party has agreed to work on such rates.  
Part-I As per schedule rate  
Part-II \_\_\_\_\_ %age above/below/at par of schedule rate
4. This agreement is valid upto **31.3.2026**.
5. In case any dispute arises between the contractor and the State Procurement Agency/FCI the matter will be referred to the Director/Director General Food and Supplies/M.D. of the concerned agency or his nominee for adjudicating the matter of dispute under the provisions of Arbitration Act, 1996 and his decision shall be binding on both the parties.

**Executants**

**Party-Ist**

**Party-IInd**

Witness -----

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

**FORMAT OF TECHNICAL BID (For Labour and Cartage Tender 2025-26).**

Sr. No.	Particulars	
1.	<p>Detail of the duly self attested Certificate to be uploaded: (Yes/No)</p> <p>i) Certificate on proper stamp paper that the contractor/tenderer has not been blacklisted by any of the Government/Semi Government Department of the State &amp; by FCI, and not connected to any blacklisted firm.</p> <p>ii) Proof of physical availability of at least 30% trucks (as applicable) with registration in the name of tenderer firm and partners of the firm submitting the tender or he/she may have agreement with any transport company/truck owners. If any firm comes L-1 in more than one tender, it will be considered for one tender only on the basis of that 30% availability of trucks details list, but if it applied with another list of 30% details (the registration number of the trucks must be different) in continuation for another mandi where it is L-1, same will be accepted for the allotment of the second tender and so on. Otherwise L-2 will be offered to work at L-1 rates. If L-2 doesn't agree, then L-3,L-4,L-5 and so on will be offered to work at L-1 rates. <u>with the remarks that if a firm falls short of physical availability of 30 % owned trucks, it will have to deposit an additional security@ <b>Rs 1,25,000/- (75,000 refundable + 50,000 non-refundable)</b> per trucks of short number of ownership of trucks after having agreement with an transport company/truck owners. <b>However this relaxation would be given only for 10% of the shortage in owned trucks.</b> The additional <b>refundable</b> security so deposited will be refundable after completion of lifting of food grains from mandi to storage points. The same will be applicable for all the tenderers. (As per terms and conditions).</u></p> <p>iii) Certified Partnership Deed in case of partnership concerns.</p> <p>iv) Solvency certificate issued by the banker.</p> <p>v) Bank statement for last six months showing turnover at least 10% of the total cost of contract of previous year of the bid business.</p> <p>vi) Letter from bank regarding credit limits enjoyed by the tenderer which should be at least 10% of the total cost of</p>	





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

	contract of previous year of the bid business. vii) Letter from the bank regarding credit/limits enjoyed. viii) Duly audited Balance Sheet/Profit & Loss account of the preceding three financial <b>year's i.e. 2021-22, 2022-23 &amp; 2023-24.</b> ix) Statement of Assets with valuation certificate from valuator along with documentary proof of immovable property other than residential house, which may not be less than 10% of the cost of contract value. x) Proof/Certificate of satisfactory work done during previous three years in the field of mandi labour and cartage work only from the concerned DFSC/DMs of the state procurement agencies & FCI having detail of volume of work done in the mandis.	
2.	Detail of Earnest Money Deposit and for Labour and Transportation payment.	RTGS...NO DATE.... NAME OF BANK..... AMOUNT.....
3	Whether the copies of the following documents duly signed at each page have been uploaded (write Yes or No)	
	i) Tender Documents and Terms & Conditions. ii) Power of attorney to sign the tender documents.	





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

**टैन्डर फार्म**  
**श्रम ढुलाई व कारटेज कार्य हेतु**  
**वर्ष 2025-26**

टैन्डर नोटिस क्रमांक:

दिनांक

1. केन्द्र का नाम जिसके लिए टैन्डर दिया जाना है
2. धरोहर राशि
3. प्रतिभूति की राशि
4. टैन्डरदाता व पार्टी का नाम
5. पिता का नाम
6. वर्तमान पता
7. स्थाई पता (As per voter list/ration card/identity card/licence)
8. मोबाईल नम्बर: ई-मेल आईडी

Affix attested  
 Passport Size  
 Photograph of  
 tenderer

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टैन्डरदाता विभाग के कार्यों के लिए बलैक लिस्टिड नहीं है व ना ही किसी ब्लैकलिस्टिड फर्म से सम्बंध है ।

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों नियन्त्रक,

सेवा में

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों नियन्त्रक

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैंने/हमने उपरोक्त वर्णित टैन्डर नोटिस की सभी धाराओं का तथा उसके साथ सभी संलग्न दरों का भली भान्ति अध्ययन कर लिया है और मैं/हम उपरोक्त वर्णित केन्द्र पर उपरोक्त वर्णित अवधि के लिए श्रम व ढुलाई का कार्य अनुबन्ध 'ए' भाग-11 के कार्य निम्नलिखित टैन्डर दरों पर करने के लिए सहमत है/हूँ ।

1. प्रतिशत उपर (ASOR)
2. बेसिक दर (SOR)
3. प्रतिशत कम दर (BSOR)

बैंक का नाम

आर टी जी एस

राशि

हस्ता0 टैन्डरदाता

**कार्यालय उपयोग के लिए**

तकनीकी बोली में सफल हाने उपरांत टैन्डरदाता का टैन्डर फार्म निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं की उपस्थिति में खोला गया

जि.प्र.

जि.प्र.

जि.प्र.

जि.खा.पू.नि. एवं उ.म0अ0(ना0)

पुलिस अधीक्षक

एफ.सी.आई

हैफेड

एच.डब्ल्यू.सी.

जि.प्र. कान्फैड

उपायुक्त / प्रतिनिधि उपायुक्त





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

**टैन्डर फार्म**

**श्रम दुलाई व कारटेज कार्य हेतु**

**वर्ष 2025-26**

टैन्डर नोटिस क्रमांक:

दिनांक

1. टैन्डरदाता व पार्टी का नाम
2. पिता का नाम
3. वर्तमान पता
4. स्थाई पता As per voter list/ration card/identity card/licence
5. केन्द्र का नाम जिसके लिए टैन्डर दिया जाना है
6. धरोहर राशि
7. बैंक का नाम आर टी जी एस राशि
8. मोबाईल नं० ई०-मेल आईडी

Affix  
attested  
Passport Size  
Photograph  
of  
tenderer

सेवा में

जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों नियन्त्रक

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैंने/हमने उपरोक्त वर्णित टैन्डर नोटिस की सभी धाराओं का तथा उसके साथ सभी संलग्न दरों का भली भांति अध्ययन कर लिया है और मैं/हम उपरोक्त वर्णित केन्द्र पर उपरोक्त वर्णित अवधि के लिए श्रम व दुलाई का कार्य अनुबन्ध 'ए' भाग-11 के कार्य निम्नलिखित टैन्डर दरों पर करने के लिए सहमत है/हूँ।

1. प्रतिशत उपर (ASOR)
2. बेसिक दर (SOR)
3. प्रतिशत कम पर (BSOR)

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ/है कि मैं/हम अथवा मेरी/हमारी फर्म/कम्पनी/सोसाईटी किसी भी विभाग/एजेंसी के कार्यों के लिए ब्लैकलिस्टिड नहीं है व ना ही मेरा किसी ब्लैकलिस्टिड फर्म से सम्बंध है

हस्ता० टैन्डरदाता

कार्यालय उपयोग के लिए

तकनीकी बोली में सफल होने उपरांत टैन्डरदाता का टैन्डर फार्म निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं की उपस्थिति में खोला गया:-

जि.प्र.	जि.प्र.	जि.प्र.	जि.खा.पू.नि. एवं उ.म०अ०(ना०)	पुलिस अधीक्षक
एफ.सी.आई	हैफेड	एच.डब्ल्यू.सी.	जि.प्र. कान्फैड	

उपायुक्त/प्रतिनिधि उपायुक्त





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

**OFFICE OF THE DIRECTOR, FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS HARYANA,  
 CHANDIGARH**

**E-TENDER NOTICE FOR LABOUR AND CARTAGE FOR THE YEAR 2025-26**

E-Tenders are invited from labour contractors other eligible entities for doing various labour and cartage operations of foodgrains/coarsegrains/oil seed/stock articles as shown in part-II of the Annexure "A" for all the mandis/godowns except in the godowns constructed/operated under FCI guarantee scheme falling in each district for the year **2025-26** in respect of State Procurement Agencies i.e. Food, Civil Supplies and Consumers Affairs Department, Haryana State Co-operative Supply & Marketing Federation (Hafed), Haryana Warehousing Corporation (HWC) and Food Corporation of India (FCI). The tenders in respect of all the State Procurement Agencies and FCI shall be received by the concerned Deputy Commissioner/Tender Committee/DFSC as follows:

Invitation of Tender	24.02.2025 at 09:00 am
Closing date of Tender	03.03.2025 till 05:00 pm
Opening of Technical Bid	04.03.2025 at 09:00 am
Opening of Financial Bids and finalization of Tender by DLTC/and send proposal to SLC if premium is higher than 10%.	06.03.2025 at 02:00 pm
<b>Re-tender ( if any)</b>	10.03.2025 at 09:00 am
Opening Date	
Closing date of re-tender	17.03.2025 till 05:00 pm
Opening of Technical Bids	18.03.2025 at 09:00 am
Opening of financial Bid and finalization of re-tender/ send proposal to SLC for finalization by DLTC (if, the premium is higher than 10%) after re-tendering	19.03.2025 at 09:00 am
Finalization of rates by SLC	26.03.2025

- If single tender is received in any mandi, re-tender will be called on very next day after closing date of the invited tender.
- If even after re-tendering twice, single tender is received for the third time, then the decision regarding opening of bid and finalization of tender on single bid as per Clause 24, may be done by DLTC.

1. The venue for receiving/opening of tenders shall be fixed by the concerned Deputy Commissioner/ Tender Committee as per details given in the tender notice.
2. Tender forms and detail terms and conditions can also be downloaded from the website of this department i.e. <http://haryanafood.nic.in>.
3. In case of any enquiry/problem, the concerned Distt. Food and Supplies Controller for Food and Supplies Department/Distt. Manager of the respected procurement agency may be contacted.





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

4. The procurement figures of Wheat, Paddy, foodgrains, pulses, mustard, bajra, coarsegrain and other articles purchased during Rabi & Kharif Marketing Season for the year **2024-25** (if required) can be obtained from the concerned Agency on any working day.
- 2 5. The District Tender Committee reserves the right to accept/reject any/all tenders without assigning any reason. After the final acceptance of the tender by the tender committee, no request for further increase of rate for any operation shall be entertained.
- Dr. Kumar

*Negme*  
13/2/25  
Joint Director (Mandi Proforma)  
for Director Food, Civil Supplies and  
Consumer Affairs Department Haryana





Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
**Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs**  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

I/we hereby state that:-

1. I/we have thoroughly read all the schedules, appendices, and annexures to the tender documents, terms & conditions carefully.
2. Our offer is as per Terms and Conditions given in the tender document.

Signature-----

Seal/Stamp

Full Name of the authorized signatory (mandatory)-----

Designation of the signatory (mandatory)-----

Contact No. of signatory (mandatory)-----

E-Mail ID of signatory-----